(ख) भारी इंजीनियरी निगम, रांची को किन-किन स्थानों से क्रय आदेश मिले हैं और इनके मूल्यों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग और लोक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थूगन) : (क) एच०ई०सी० के लिए इस वर्ष किए गए बजट प्रावधान तथा उनको अब तक दी गई धनराशि का विवरण नीचे दिया गया है :—

(करोड़ रुपए में)

	बजट प्रावधान	दी गई धनराशि
योजना	3.00	1.50
गैर-योजना	11.35	7.00
स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना	19.00	12.00

(ख) एच.ई.सी. के प्रमुख ग्राहक इस्पात, खनन, पावर, रक्षा तथा रेलवे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से है । इन क्षेत्रों से 1-4-1991 से 30-6-1992 तक प्राप्त क्रयादेशों का मूल्य निम्न प्रकार है :-

क्षेत्र	(मूल्य करोड़ रुपये में)
इस्पात	160.14
खनन	172.25
पावर	2.00
रक्षा	10.91
रेलवे	4.60
अन्य	10.88
योग	360.78

Proposals by foreign investors to set up projects in India

1530. SHRI VITHALBHAI M. PATEL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a number of proposals have been received by the Central Government from foreign investors to set up projects in India;

(b) what is the number of proposals received to set up projects in India by foreigners during last two years;

(c) what is the number of proposals that have been cleared-with details thereof;

(d) what is the number of proposals pending for disposal; and

(e) what are the reasons for delay in clearing the proposals received from overseas?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The details of proposals for foreign collaboration cleared during the period 1990 till June, 1992 are as under:—

(i) Year	1990	1991	1992 (upto June)
(ii) Total number of foreign collaboration proposals cleared	666	950	796
(iii) Number of foreign collaboration proposals involving foreign investment cleared	194	2·89	317
(iv) Total amount of foreign investment involved	128·32 crores	534·11 crores	1475·96 crores

These include proposals for foreign collaboration received during the last two years.

(d) The number of applications for financial foreign collaboration pending as on 30th June, 1992 was 98.

(e) The main reasons for pendency of these applications is either these are not yet ripe for consideration by the concerned Approval Boards or are awaiting comments of concerned administrative ministries or other scrutinising agencies or their consideration has been deferred by the concerned Approval Boards for re-examination of certain aspects of the proposal, by the concerned scrutinising agencies.

Manufacture of gas, hydro steam turbines

1531. SHRI VIREN J. SHAH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have removed the ceiling on the manufacture of gas hydro/steam turbines and their respective generating sets of 60 MW capacity;

(b) if so, what are the details in this regard; and

(c) whether it would affect BHEL and benefit its foreign competitors?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY AND DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES) (SHRI P. K. THUNGON): (a) and (b) Yes, Sir. As per the New Industrial Policy announced vide Notification No. 412 dated 25-7-1991, the manufacture of gas, hydro, steam turbines and their associated generators, irrespective of the size has been exempted from the provisions of Industrial Licensing. These item(s) of manufacture are also not reserved for manufacture in the small scale sector or the public sector undertakings, under the New Policy.

(c) The environment will become more competitive.

उद्योगों को संरक्षण

1532. **श्री राजूभाई ए. परमार :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार ने एक नीति अपनाई है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस नीति से कौन-कौन से उद्योग लाभान्वित हुए हैं ;

(घ) ऐसे उद्योगों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने संरक्षण की नीति के तहत लाभ उठाया है लेकिन वे संरक्षण प्राप्त करने की शर्तों का पालन नहीं कर रहे है; और

(ङ.) ऐसे उद्योगों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ङ.) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 में, लघु क्षेत्र में उत्पादन के लिए जिन 836 मदों को आरक्षित किया गया है, उनके बारे में मझौली तथा बड़ी एककों द्वारा किसी अतिक्रमण के विरुद्ध लघु उद्योगों के संरक्षण की व्यवस्था है । इन मदों का ब्यौरा दिनांक 25 जुलाई, 1991 की बजट अधिसूचना सं० 577(अ) की अनुसूची 3 में दिया है । केवल लघु क्षेत्र में निर्माण के लिए मदों के आरक्षण की नीति का उल्लंघन उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन एक दण्डनीय अपराध है ।